(a) and (b). M/s Edward Textile Mills, Bombay was taken over by the Government of Maharashtra on a leave and license basis w. e. f. 1.5.1969 on which date the above establishment was in default of payment of provident fund contributions of a sum of about Rs. 14.95 lakhs comprising of Rs. 10 05 lakhs as past Provident Fund accumulations, Rs. 4.46 lakhs as employer's share and Rs. 0 44 lakhs as worker's share. As the Mill has gone into liquidation, a claim has been filed with the Official Liquidator for the entire amount of Provident Fund dues. The cases under Section 406/409 of the I. P. C. against the management are pending in the Court.

बगला देश से आये शरणार्थियों को मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में बेहानी में बसाया जाना

*1731. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बगला देश से आये शरणार्थियों को मोरेना जिले के बेहानी क्षेत्र में बसाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है और वहां कितने शरणार्थियों को बसाने का प्रस्ताव है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ; और

(ग) शरणार्थियों को वहां कब तक बसाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं, । मोरेना जिले के बेहानी क्षेत्र में बंगला देश के शरणार्थियों को बसाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासी कृषक परिवारों के (जो 26 मार्च, 1971 से पूर्व आये थे) मध्य प्रदेश में मोरेना जिले की शिओपुरी तहसील में तंगघाटी भूमि क्षेत्र के उद्धार के उपरान्त, पुनर्वास के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बात-चीत हुई है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने, मोरेना जिले की शिओपुरी तहसील में लगभग 20,000 एकड़ तगघाटी भूमि क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण और क्षेत्र के उद्धार के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार को 7.80 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया है । परियोजना रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर योजना का ब्यौरा तैयार किया जायेगा ।

New Pay Scales for Agricultural Scientists

*1732. SHRI PRABHUDAS PATEL :
SHRI K. MALLANNA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Ministry has decided to give a new content and meaning to agricultural research and education during the Fourth Plan ;

(b) if so, whether the Indian Council of Agricultural Research is currently working out plans to implement new pay scales for agricultural scientists which at present are comparatively lower than those of the scientists working in other scientific organisations ; and

(c) if so, when the final decision in this regard is likely to be taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Indian Council of Agricultural Research is being re-organised with a view to making it an autonomous Central agency responsible for promoting, coordinating and directing research and education in the field of agriculture and animal sciences through out the country. As one of the basic principles and objectives of the scheme of reorganisation is to improve the working conditions of agricultural research scientists, efforts have been made from the very initial stage of reorganisation of the Council at improving the scales of pay of agricultural scientists. The pay scales of a number of posts at the Council's headquarters and in the Research Institutes under it, have been upgraded since reorganisation.